(ii) आने-जाने वालों के लिए रेलवे स्टेशनों का पहुच से बाहर होना ।

(iii) डी० टी० सी० फीडर सेवा की अपर्याप्तता ।

(iv) मार्गस्थ यात्रा में अधिक प्रतिक्षा/पंक्तियों में लगना जो इस समय काफी अधिक है ।

(v) दिल्ली से जाने वाली परिधीय वाहनों पर रिंग रेलवे पर ई० एम० यू० सेवा का विस्तार न होना, इस तरह से दिल्ली क्षेत्र में विस्तृत रेल नेट वर्क पर रेल सेवाओं का एक अंगभूत भाग नहीं बन पा रहा है ।

(ख) दल्वी समिति द्वारा रिंग रेलवे पर रेल सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए दिये गये सुझाव इस प्रकार थे :—

(i) रिंग रेलवे पर ई० एम० यू० सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि ।

(ii) रिंग रेलवे में ई० एम० यू० सेवाओं का 3 परिधीय वाहनों अर्थात् दिल्ली/नई दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली/नई दिल्ली से शकूरबस्ती, दिल्ली/नई दिल्ली से पलवल जिनका पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है, तक विस्तार ।

(iii) उन अन्य परिधीय लाइनों का विद्युतीकरण जिनका अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है और उन पर ई० एम० यू० सेवाएं चलाना । रिंग रेलवे पर ई० एम० यू० सेवाओं में वृद्धि करने के प्रश्न पर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और इस तथ्य के कारण कि रिंग रेलवे वस्तुतः मात्र यातायात को गुजारने के लिये दिल्ली से बचकर निकलनेवाली लाइन है, इसलिए ई० एम० यू० सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

जहां तक विद्युतीकरण परिधीय लाइनों में ई० एम० यू० सेवाओं की बारम्बरता में विस्तार/वृद्धि या जिन परिधीय लाइनों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनका विद्युतीकरण करना और उन पर ई० एम० यू० सेवाएं चलाने का संबंध है, यह बताया जाता है कि यह निधियों की उपलब्धता तथा इन परिधीय लाइनों की क्षमता पर भी निर्भर करेगा ।

Development of land by Everest Himalaya Cooperative Group Housing Society Ltd.

2347. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while alloting land in 1984 at Plot No. 8 Patpar Ganj to the Everest Himalaya Cooperative Group Housing Society Ltd., the DDA promised to develop the plot in due course;

(b) whether it is also a fact that despite several requests made to the DDA the land was not developed by them and ultimately it was developed by the Society Members themselves on the understanding that the cost would be reimbursed by the DDA;

(c) whether the cost of development has since been reimbursed to the Society by the DDA; and

(d) if not, what are the reasons for the delay and by when the Society is likely to get the amount spent by it on the development of the land as per the original agreement with the DDA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) DDA is responsible to provide peripheral services in Zone E-13 where a plot has been allotted to Everest Himalaya Cooperative Group Housing Society Ltd. along with other Societies. No development is to be done by the DDA within individual plot. As such there is no question of any agreement with or reimbursement of cost by the DDA.

Declaration of rivers as national assets

2348. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare rivers of the country as national